

भारत सरकार  
भारी उद्योग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1227  
11.02.2025 को उत्तर के लिए नियत

भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र

1227. श्री दुरई वाहको:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की योजना" के अंतर्गत इस योजना के आरंभ से लेकर अब तक तिरुचिरापल्ली और पुडुकोट्टई जिलों में आरंभ किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजना के आरंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र चरण-II में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की स्कीम के अंतर्गत, भारी उद्योग मंत्रालय ने उन्नत वेल्डिंग प्रौद्योगिकियों में कौशल प्रदान करने के लिए वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान (डब्ल्यूआरआई), त्रिची-बीएचईएल में एक सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (सीईएफसी) को मंजूरी दी है। कुल परियोजना लागत 87.06 करोड़ रुपये है, जिसमें से एमएचआई अनुदान 69.648 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के तहत, अब तक 7000 से अधिक वेल्डिंग पेशेवरों

को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह एक अखिल भारतीय मांग आधारित स्कीम है और इस स्कीम में राज्य-वार वितरण/ब्यौरे अनिवार्य नहीं हैं।

(ख): "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र चरण-I और II में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि" स्कीम के तहत आवंटित निधियों और इसके उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ रु.में)

वित्तीय वर्ष	स.अ. स्तर पर आबंटन	जारी की गई निधि
2014-15	24.00	2.80
2015-16	23.00	22.87
2016-17	60.50	59.97
2017-18	110.00	109.72
2018-19	110.50	110.4483
2019-20	102.30	102.16184
2020-21	55.52	54.2197
2021- 22	29.00	28.933925
2022-23	199.60	199.24
2023-24	187.20	83.3431
2024-25	120.00	134.55
	184.00 *	( 03.02.2025 के अनुसार )

\* वर्तमान आवंटन